सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. नंबर MPBIL/2015/66535

*NewsPaper*NewsPortal*NewsChannel

डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

DGR Detective Group Report

सतर्क रहें-सजग रहें अभियान

www.dgr.co.in | www.detectivegroupreport.com

वर्ष : 12 अंक : 02 | इंदौर, बुधवार 22 जुलाई, 2026 | पेज : 8, मूल्य : 2 रुपए

विपक्ष का प्रोटेस्ट पार्ट-2...

काले कपड़ों में संसद पहुंचे सभी मप्र, राहुल-प्रियंका-अखिलेश ने संभाली कमान

नई दिल्ली, (एजेंसी) कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को संसद भवन के मकर द्वार पर काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. ये प्रदर्शन नीट पेपर में धांधली के खिलाफ छात्रों के आंदोलनों और शिक्षा व्यवस्था में जारी अशांति से निपटने के सरकार के तरीके के खिलाफ आयोजित किया गया है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य सांसदों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और जंतर-मंतर पर सीजेपी कार्यकर्ताओं व छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों ने एक साथ आकर अपनी नाराजगी जताई है.

बताया जा रहा है कि कांग्रेस के इस बड़े विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और कड़ा संदेश देना है. पार्टी सांसदों ने एक साथ एकजुट होकर विरोध जताने की रणनीति बनाई है.

संसद भवन परिसर में आयोजित कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुईं प्रियंका ने कहा कि हमारे साथ जो हुआ, वह अहम नहीं है. आप (मीडिया) मुझे बताएं कि छात्रों के साथ जो हुआ, वह सही है या गलत? छात्रों की मांगें जायज हैं और वो अपने हक की बात कर रहे हैं. शिक्षा का बजट 1.4 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन आप अडानी और अंबानी का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर रहे हैं. छात्रों का संघर्ष जायज है और वह बदलाव चाहते हैं. बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं... शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में कुछ भी अलोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन छात्रों और संसद में जो हो रहा है, वह अलोकतांत्रिक है.

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने बताया कि सभी विपक्षी सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों और सांसदों पर पुलिस के इस्तेमाल के विरोध में काले कपड़े पहनकर आए हैं.उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार हठ छोड़कर छात्रों से संवाद करे और पूरी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे.

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कड़ा आक्रोश जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना नेम टैग वाले लोग आकर हमला करते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष इस बर्बरता पर चुप बैठे रहें और अपनी आवाज न उठाएं.

मध्यप्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल हो गया पास

शादी-लिव इन समेत कई नियम बदल जाएंगे

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

भोपाल, एजेंसी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के विरोध के बीच ध्वनि मत से समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। मुख्य विपक्षी दल ने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ और राजनीतिक एजेंडा बताते हुए विरोध दर्ज कराया। इसके बावजूद सरकार ने बिल को सदन से पास करा लिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने वाला देश का पांचवां राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा (आजादी के समय से), उत्तराखंड, गुजरात और असम में यूसीसी लागू है।

विधानसभा में बिल को पेश करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा में एक सुनहरा इतिहास

रचा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी तुष्टिकरण की राजनीति और इसे आदिवासी-विरोधी बताने के कारण इस मौके को गंवा रही है।

कांग्रेस की एक मांग को किया नामंजूर

उधर सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने बिल का विरोध किया और पार्टी विधायक आरिफ मसूद की उस मांग का समर्थन किया जिसमें बिल को चर्चा के लिए एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि UCC बिल पास करने के बजाय, भाजपा सरकार को OBC समुदाय के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए।

विपक्षी विधायक विरोध करते हुए वेल में पहुंच गए

यादव का भाषण पूरा होने के बाद, स्पीकर (विधानसभा अध्यक्ष) नरेंद्र सिंह तोमर ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल से बिल को ध्वनि मत से पास कराने के लिए पेश करने को कहा। जिसके बाद विपक्षी विधायकों के सदन के बीचों-बीच (वेल में) विरोध जारी रखने के बावजूद बिल पास हो गया।

सोमवार को सदन में रखा गया था बिल

इससे एक दिन पहले मध्यप्रदेश सरकार ने सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक-2026 का पेश किया था, जिसमें बहुविवाह पर रोक तथा सभी धर्मों के लिए विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रावधान है।

'मुस्लिम महिलाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा'

बिल पेश करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा और इससे उनके जीवन की कई समस्याओं, जैसे हलाला का समाधान होगा। यादव के अनुसार राज्य में 'राम, रहीम और रॉबिन' समेत सभी के लिए एक समान कानून जरूरी है। इससे पहले रविवार को मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने यूसीसी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी थी। प्रस्तावित कानून में तीन तलाक और निकाह हलाला को दंडनीय बनाने, बहुविवाह पर रोक लगाने तथा एक महीने के भीतर सहजीवन (लिव-इन रिलेशनशिप) का पंजीकरण नहीं कराने पर तीन महीने तक के कारावास का प्रावधान किया गया है।

कटाक्ष

इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल क्यों नहीं? मध्यप्रदेश हाई कोर्ट सख्त

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट, (नप्र)

इंदौर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य के सबसे बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक शहर इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

यह नोटिस 'मध्य प्रदेश टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन' की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। याचिका में बताया गया कि पूरे प्रदेश के लिए जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्यपीठ केवल भोपाल में बनाई गई है। जबकि 18 दिसंबर 2019 को हुई जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में इसे इंदौर में स्थापित करने का फैसला लिया गया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएन गोयल और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यश तिवारी ने दलील दी कि इंदौर में पहले से हाई कोर्ट की खंडपीठ और राज्य जीएसटी आयुक्त का मुख्यालय है। सबसे अधिक जीएसटी राजस्व देने वाले शहर को नजरअंदाज करना अनुचित है। अदालत में दलील दी गई कि देश के कई राज्यों में एक से अधिक शहरों में ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी यह मुद्दा संसद में उठाया था। तब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया था कि केंद्र को इंदौर में ट्रिब्यूनल खोलने से कोई आपत्ति नहीं है, बस राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजना होगा। आरोप है कि राज्य सरकार ने अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। इंदौर के व्यापारिक संगठनों का कहना है कि ट्रिब्यूनल न होने से टैक्स विवादों के निपटारे के लिए व्यापारियों और करदाताओं को बार-बार भोपाल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। याचिका में इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार) और 21 का उल्लंघन बताया गया है। अब हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद गेंद सरकार के पाले में है।

जनसुनवाई बनी जनविश्वास का आधार, हर जरूरतमंद तक पहुंची प्रशासनिक सहायता

जनसुनवाई में समस्याओं का त्वरित निराकरण

हितग्राहियों ने कलेक्टर श्री शिवम वर्मा का जताया आभार

गंभीर नदी के पुनर्जीवन से किसानों के जीवन में वापस आ रही है खुशहाली

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट, (नप्र)

इंदौर। कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार आयोजित हो रही साप्ताहिक जनसुनवाई आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं संवेदनशील निराकरण का प्रभावी माध्यम बन रही है। जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर शिवम वर्मा के समक्ष रखीं। कलेक्टर श्री वर्मा ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा पात्र हितग्राहियों को तत्काल राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। जनसुनवाई के माध्यम से प्रशासन निरंतर आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित कर रहा है। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, रोशन राय, रिंकेश वैश्य सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याओं को सहानुभूति के साथ सुना और उनका निराकरण किया।

कलेक्टर श्री वर्मा का किसानों ने साफा एवं पुष्पहार पहनाकर जताया आभार- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार इंदौर जिले में गंभीर नदी को पुनर्जीवन देने का कार्य तेजी से जारी है। प्रारंभिक चरण में ही इसके सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। अल्प वर्षा में ही नदी में और आसपास के खेतों के कुंओं में पानी ठहरने लगा है। अपने सुखद भविष्य की शुरूआत होते देख किसानों में खुशी की लहर है। आज इस नदी से जुड़े कैलोद गाँव के किसान बड़ी संख्या में एकत्र होकर कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और उन्होंने शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में आज आयोजित जनसुनवाई में पहुँचे किसानों ने कलेक्टर शिवम वर्मा का गंभीर नदी पुनर्जीवन परियोजना को अमली रूप देने पर साफा एवं पुष्पहार पहनाकर हृदयपूर्ण आभार व्यक्त किया। इस दौरान ग्राम कैलोद के सरपंच कमल चौधरी, जनपद सदस्य महू विलीन पाटीदार सहित ग्राम के कृषकगण उपस्थित रहें। उल्लेखनीय है कि गंभीर नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि मालवा अंचल की जीवनरेखा है। इसके संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों तथा स्थानीय कृषकगणों की सक्रिय भागीदारी से उक्त कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देकर गंभीर नदी को पुनः अविरल और निर्मल बनाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किया जा रहा है। नदी तटों पर वृक्षारोपण, जलग्रहण क्षेत्र विकास, कंटूर ट्रेंच, बोल्डर चेकडैम, लूज बोल्डर संरचनाएं, रिचार्ज शाफ्ट, खेत तालाब तथा अन्य जल संरक्षण कार्यों की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

जनसुनवाई में पहुंचे कैलाशचंद्र लाड़वा ने कलेक्टर शिवम वर्मा के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत अपनी समस्या के त्वरित एवं संतोषजनक निराकरण के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कलेक्टर श्री वर्मा को पुष्पमाला पहनाकर शासन-प्रशासन के प्रति अपनी आभार व्यक्त किया। श्री लाड़वा ने कहा कि जनसुनवाई आमजन के लिए आशा और विश्वास का केंद्र बन गई है, जहां प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुनकर उसका समयबद्ध समाधान किया जा रहा है।

इसी क्रम में श्रीमती शेराबाई मौर्य अपनी पोतियों के साथ जनसुनवाई में पहुंचीं और कलेक्टर शिवम वर्मा को अपनी पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि चार वर्ष पूर्व उनके पोते स्व. शिवम मौर्य का निधन हो गया था। उनके दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक 6 वर्षीय पुत्र एवं एक 8 वर्षीय पुत्री है। पोते के निधन के बाद से दोनों बच्चों का पालन-पोषण एवं भरण-पोषण की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही है, जबकि मेरी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। इस प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल 24 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। बच्चों की शिक्षा के लिए भी निर्देशित किया।

एक अन्य प्रकरण में मानसिंह जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर शिवम वर्मा के समक्ष अपनी समस्या रखी। उन्होंने बताया कि मशीन पर कार्य करने के दौरान हुई दुर्घटना में हाथ की चारों उंगलियां कट गई थीं, जिसके कारण मैं, कार्य करने में असमर्थ हूँ और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा हूँ। उनकी स्थिति को गंभीरता से देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को 10 हजार रुपए की तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा उनका निःशुल्क उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें शीघ्र राहत मिल सके।

कलेक्टर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में अधिकारियों ने आमजन से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशन में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कई आवेदन प्राप्त हुए जिसमें मुख्य रूप में प्लॉट, संपत्ति, पारिवारिक विवाद, चिकित्सा सहायता और रोजगार से जुड़े प्रकरण रहे।

शासकीय भूमि एवं नाले से अतिक्रमण हटाया

इंदौर। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में तहसील जूनी के अंतर्गत ग्राम मुंडलानायता में शासकीय भूमि एवं नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम मुंडलानायता की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 28, रकबा 0.560 हेक्टेयर पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। उक्त कार्रवाई राजस्व विभाग, नगर निगम एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर टीन शेड, बाउंड्री वॉल तथा अन्य अवैध निर्माणों को हटाते हुए शासकीय भूमि एवं नाले पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया। बताया गया कि शासकीय भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग की परिसंपत्तियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा इस प्रकार के मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सैकड़ों छात्र धरने पर, नीट पेपर लीक पर फूटा गुस्सा

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट, (नप्र)

इंदौर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक प्रकरण को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए व्यापक छात्र प्रदर्शन की गूंज अब मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी प्रमुखता से सुनाई देने लगी है। शहर के प्रसिद्ध भंवरकुआं चौराहे पर जारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में न केवल स्कूल और कॉलेजों के छात्र-छात्राएं शामिल हो रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय कलाकार और आम नागरिक भी अपनी एकजुटता दिखाने पहुंच रहे हैं। यह पूरा समूह अपनी मांगों को लेकर सोमवार रातभर चौराहे पर ही धरने पर डटा रहा। आंदोलनरत प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की पुरजोर मांग की और देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार लाने की बात कही। इसके साथ ही दिल्ली में अनशन पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा बलपूर्वक अस्पताल ले जाए जाने की घटना का तीखा विरोध जताया गया तथा पूर्व में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। भंवरकुआं चौराहे पर जारी इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले के तनाव और हताशा के कारण आत्महत्या करने वाले 20 होनहार विद्यार्थियों के नामों वाला एक विशेष पोस्टर प्रदर्शित किया और मोमबत्तियां जलाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विरोध जताने के अनूठे अंदाज में दो छात्राओं ने आंदोलन के मुख्य प्रेरणास्त्रोत सोनम वांगचुक की एक बड़ी और आकर्षक रंगोली बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस जमीनी आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा नेता सक्षम असाटी और अरुण बड़ोले ने स्पष्ट किया कि यह विरोध प्रदर्शन किसी भी राजनैतिक दल से प्रेरित या संचालित नहीं है। यह विशुद्ध रूप से देश के लाखों छात्रों के उज्ज्वल भविष्य और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर किया जा रहा एक संवैधानिक व लोकतांत्रिक प्रदर्शन है। इस आंदोलन को संबल देने के लिए एक सौ एक वर्षीय वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पूर्व सांसद पंडित रामकृष्ण शर्मा तथा वयोवृद्ध समाजवादी नेता रामबाबू अग्रवाल भी खुद धरना स्थल पहुंचे और छात्रों के हौसले की सराहना की।

नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन

इंदौर। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इंदौर में प्राचार्य डॉ. बी. डी. श्रीवास्तव के संरक्षण, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. वी. पी. बैरागी के मार्गदर्शन में, कार्यक्रम के संयोजक प्रो. सुधीर कुमार छारी के निर्देशन में 21 जुलाई को "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में पुलिस विभाग की ओर से डी.एस.पी श्रीमती आशा सेजकर, निरीक्षक शहनाज बानो, उप निरीक्षक आशीष शर्मा सहित लगभग 20 पुलिस अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे। अधिकारियों ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने छात्राओं से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। अभियान के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशामुक्त समाज के संदेश को निबंधों के माध्यम से समाज को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। निबंध प्रतियोगिता के लिए डॉ. नेहा गुप्ता एवं प्रो. सादिक खान ने अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया तथा प्रतियोगिता को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि "नशामुक्त युवा ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की आधारशिला हैं। ऐसे जागरूकता अभियान विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी डॉ. वी.पी. बैरागी ने दैनिक जीवन की घटनाओं के उदाहरणों के माध्यम से छात्राओं को जागरूक करवाया। कार्यक्रम में छात्राओं ने भी मंच के माध्यम से नशे से दूर रहने हेतु स्लोगन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए।

महाविद्यालय परिवार ने पुलिस विभाग के इस सराहनीय अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के साथ-साथ उन्हें स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता में प्रथम कु. शिखा लोधी, द्वितीय कु. दुर्गा शर्मा एवं तृतीय कु. अनन्या भदौरिया को डी.एस.पी आशा सेजकर, निरीक्षक शहनाज बानो, उपनिरीक्षक आशीष शर्मा ने मेडल एवं प्रमाण पत्र और प्रतिभागी सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक प्रो. सुधीर कुमार छारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों की सराहना की तथा छात्राओं से अपने परिवार एवं समाज में भी नशामुक्ति का संदेश पहुँचाने का आह्वान किया गया। महाविद्यालय परिवार ने इस अभियान को जन-जागरूकता की दिशा में एक सार्थक पहल बताया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रो. सादिक खान द्वारा किया गया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी डॉ. नेहा गुप्ता द्वारा दी गई।

जूनी कसेरा बाखल में डॉक्टर का 90 साल पुराना मकान तोड़ा

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट, (नप्र)

इंदौर। नगर निगम ने डॉक्टर के करीब 90 साल पुराने मकान को जमींदोज कर दिया। मंगलवार को ये कार्रवाई जूना कसेरा बाखल में हुई। पोकलेन मशीन लेकर निगम का अमला पहुंचा। मशीन के एक ही पंजे में वहां धूल का गुबार उड़ने लगा।

नगर निगम लगातार जर्जर मकानों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में आज ये कार्रवाई की गई। ये मकान करीब 90 साल पुराना हो चुका था और काफी जर्जर हालत में था। बारिश में जर्जर मकान गिर ना जाए और कोई घटना ना हो जाए, इसे देखते हुए कार्रवाई की गई। नगर निगम ने कई ऐसे जर्जर मकानों को चिह्नित किया है। कई ऐसे जर्जर मकान है, जिन्हें पूर्व में भी तोड़ा जा चुका है। बिल्डिंग ऑफिसर पल्लवी पाल ने बताया कि निगम आयुक्त के आदेश पर जोन नंबर 3 में जूनी कसेरा बाखल में डॉ. प्रमोद साकी का मकान 80-90 साल पुराना था, जिस पर आज रिमूवल की कार्रवाई की गई। निगम का अमला पोकलेन मशीन लेकर यहां पहुंचा। सुरक्षा की दृष्टि से निगम ने आवाजाही भी बंद कर दी थी। वहीं आसपास के लोगों को भी टीम ने अलर्ट कर दिया था। जिसके बाद निगम ने कार्रवाई की।

आयुक्त द्वारा जनसुनवाई : जनसुनवाई में 48 आवेदन हुए प्राप्त

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट, (नप्र)

इंदौर। आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा निगम मुख्यालय में जनसुनवाई की गई। उक्त क्रम में मंगलवार को निगमायुक्त द्वारा स्वंय अपने कक्ष में निगम के समस्त अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अधीक्षण यंत्री एवं विभाग प्रमुख के साथ जनसुनवाई की गई। इस अवसर पर आयुक्त द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को तत्काल निराकरण करने के भी निर्देश दिये गये। आयुक्त क्षितिज सिंघल द्वारा निगम मुख्यालय स्थित कक्ष में जनसुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा राजस्व, मार्केट, भवन अनुज्ञा, स्वास्थ्य विभाग, रिमूव्हल विभाग, सीवरेज विभाग, जनकार्य विभाग सहित अन्य विभागों के 48 आवेदन आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए गए। आयुक्त द्वारा नागरिकों को समक्ष में सुना गया तथा प्राप्त आवेदन को आयुक्त कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अपर आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त व विभाग प्रमुख को तत्काल प्रेषित कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

ऑर्बिट मॉल के पास गाड़ी टकराने पर विवाद, युवक पर चाकू से हमला

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट, (नप्र)

इंदौर। सड़क पर मामूली विवाद अब जानलेवा हमलों का कारण बनते जा रहे हैं। ताजा मामला ऑर्बिट मॉल के पास का है, जहां गाड़ी टकराने की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, प्रशांत खिलची किसी निजी काम से जा रहे थे। इसी दौरान ऑर्बिट मॉल के पास स्थित एक वाइन शॉप के सामने उनकी गाड़ी टकराने की बात को लेकर कुछ युवकों से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने धारदार चाकू निकालकर प्रशांत पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल प्रशांत को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के बयान के आधार पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी कुणाल उर्फ भीम, लोकेश, हिमेश, रितेश और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरा विवाद गाड़ी टकराने की बात को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है।

सतर्क रहें-सजग रहें अभियान
★ NewsPaper ★ NewsPortal ★ NewsChannel
www.dgr.co.in
www.detectivegroupreport.com
DGR Detective Group Report
YouTube Detective Group Report
SUBSCRIBE
समाचार, विज्ञापन एवं एजेंसी के लिए संपर्क करें :- 9111156060
dgrnewsnetwork@gmail.com

मुख्यमंत्री से मिले पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस कम्पनी के पदाधिकारी

लगभग 6 हजार 200 करोड़ निवेश कर प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेगी कम्पनी

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

भोपाल, एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मेसर्स पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मंजुल शरद शाह एवं उनके सहयोगियों ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों का स्वागत किया और कहा कि वे खुले मन से मध्यप्रदेश में निवेश करें, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। भेंट के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग (मप्र शासन) और कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) साईन कर आदान-प्रदान किया गया। कम्पनी का कन्ट्री हेड क्वार्टर (कॉर्पोरेट ऑफिस) नवी मुम्बई में है। कंपनी ऑप्टिकल सिस्टम्स का उत्पादन करती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया गया कि पारस कंपनी को प्रदेश की सेमीकंडक्टर पॉलिसी बेहद पसंद आई है और अपनी यूनिट लगाने के लिए कंपनी ने भूमि भी पसंद कर ली है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम सेलवेंद्रम, प्रबंध निदेशक, मप्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड चन्द्रमौली शुक्ला एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कम्पनी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को बताया कि वे मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करना चाहते हैं। शुरूआती दौर में कम्पनी करीब 6 हजार 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस परियोजना से 2500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि कम्पनी द्वारा भूमि का चयन कर लिया है। जल्द ही भूमि आवंटन के लिए भी प्रस्ताव देंगे।

भारत की अग्रणी रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक

मेसर्स पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीस लिमिटेड भारत की अग्रणी रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, जो रक्षा, अंतरिक्ष एवं एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए स्वदेशी तकनीकों एवं उच्चस्तरीय इंजीनियरिंग समाधान विकसित एवं निर्मित करती है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है तथा कम्पनी के इक्विटी शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध हैं। कंपनी को रक्षा एवं उच्च परिशुद्धता विनिर्माण क्षेत्र में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है तथा कंपनी का वर्तमान मार्केट कैपिटलाईजेशन लगभग 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक है। कंपनी द्वारा ऑप्टिक्स एवं ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ईओ/आईआर सिस्टम, एंट्री ड्रोन सिस्टम्स, आरएफ एवं माइक्रोवेव सिस्टम, ईएमपी प्रोटेक्शन सिस्टम, क्वान्टम टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एवं हेवी इंजीनियरिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। कंपनी के विनिर्माण एवं इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तेलंगाना राज्यों में संचालित हैं। यह कंपनी रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ, इसरो, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को तकनीकी समाधान उपलब्ध करा रही है। कंपनी द्वारा वर्तमान में सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में संभावनाओं का विस्तार किया जा रहा है।

पीएम-शिक्षा मंत्री पर पोस्ट की तो माफी मंगवाई

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

मंदसौर, एजेंसी। आदिवासी युवक ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर पोस्ट की तो कुछ लोगों ने उसके साथ गाली-गलौज की। जातिसूचक अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। माफी मांगने पर ही उसे छोड़ा गया। मामला मंदसौर जिले में सोमवार का है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया। इसमें कुछ युवक पीड़ित से हाथ जोड़कर माफी मंगवाते नजर आ रहे हैं। एक युवक कह रहा है कि जो लोग पोस्ट कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहते हुएअगर शर्म आ रही हो न तो आप भारत छोड़ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं। हमारे जैसे कार्यकर्ता अगर पहुंच गए न तो पेंट गीली हो जाएगी।

सीएम से मिले शाजापुर के पेंशनर

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

भोपाल, एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में शाजापुर विधायक अरूण भीमावद के नेतृत्व में शाजापुर जिले के प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन के एक वृहद प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी पेंशनर्स के हित में सरकार द्वारा लिए गए अनेक कल्याणकारी निर्णयों की सराहना की। विशेषकर पेंशनर्स को मंहगाई राहत घोषित करने के लिए मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सरकार दोनों की सहमति जरूरी होने संबंधी पिछले 25 साल से चले आ रहे महत्वपूर्ण मसले का बेहद सकारात्मक समाधान निकालने के लिए पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय आभार व्यक्त कर अभिनंदन किया।

बर्ड ट्रेड गिरोह की महिला तस्कर बंदी

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

भोपाल, एजेंसी। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ), मध्यप्रदेश की इंदौर इकाई ने वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध अभियान में लगातार सफलता प्राप्त करते हुए अंतर्राज्यीय बर्ड ट्रेड गिरोह की 9वीं मुख्य आरोपी सविताबेन (पतिः विनोद दंतानी, निवासी अहमदाबाद, गुजरात) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले तीन वर्षों से फरार चल रही थी। सविता बेन को 20 जुलाई 2026 को इंदौर में गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि गिरोह मध्यप्रदेश से संरक्षित प्रजाति के पक्षियों (तोतों) का अवैध परिवहन कर उन्हें गुजरात के विभिन्न शहरों में ऊंचे दामों पर बेचता था। विशेष न्यायालय, इंदौर में प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। प्रकरण की विस्तृत विवेचना जारी है। बर्ड- ट्रेड गिरोह के विरुद्ध जारी कार्रवाइयों की श्रृंखला में 20 जुलाई 2026 को के 8वें आरोपी अहमदाबाद निवासी आशीष को गिरफ्तार किया गया था।

मीनाक्षी नटराजन हाईकोर्ट पहुंचीं

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

भोपाल, एजेंसी। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव परिणाम को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को जबलपुर पहुंचीं मीनाक्षी नटराजन ने बताया कि उन्होंने निर्धारित 45 दिनों की समय-सीमा के भीतर चुनाव याचिका दायर कर दी है और जल्द ही इस पर सुनवाई होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी द्वारा उनका चुनावी दावा खारिज किया जाना पूरी तरह गलत है।

पुलिस चौकी में होम गार्ड ने लगाई फांसी

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

छिंदवाड़ा, एजेंसी। जुन्नारदेव थाना क्षेत्र की अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ नगर सैनिक दिलीप बाथे (55) का शव मंगलवार दोपहर में चौकी के एक कमरे में फंदे पर मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।जानकारी के अनुसार, दिलीप बाथे ड्यूटी खत्म होने के बाद चौकी में ही थे। उनका शव सबसे पहले चौकी में मौजूद कर्मचारियों ने फंदे पर लटका देखा। इसके बाद साथी नगर सैनिकों ने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि दिलीप बाथे पिछले पांच दिनों से घर नहीं गए थे। शुरुआती तौर पर उन्होंने ड्यूटी के दबाव की बात कही है। हालांकि, उन्होंने किसी पर कोई आशंका नहीं जताई है। जानकारी के अनुसार, दिलीप बाथे पिछले करीब 10 वर्षों से अंबाड़ा पुलिस चौकी में पदस्थ थे।

सिर मुंडवाकर धरने पर बैठी महिला

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

विदिशा, एजेंसी। गांधी चौक नीमताल पर मंगलवार को महिला ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरना दिया। महिला का सिर मुंडा हुआ था और उसके हाथ में विरोध से जुड़े स्लोगन लिखी तख्तियां थीं। वह केंद्र सरकार से पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांग रही थी। धरना देने वाली महिला की पहचान रायपुरा नई बस्ती निवासी शिवानी अहिरवार के रूप में हुई है। वह शहर के एक निजी होटल में कार्यरत हैं। शिवानी ने कहा कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई दुखद है। उनके अनुसार, छात्र देश का भविष्य हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए।

पति बोला-सरकारी अफसर बनने के बाद पत्नी ने छोड़ा

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

भोपाल, एजेंसी। सरकारी विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद पत्नी ने पति पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए और बच्चे के साथ मायके चली गई। उसने शादी के 20 साल बाद महिला आयोग में शिकायत करते हुए तलाक भी मांग लिया। सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर पति को आयोग ने सुनवाई के लिए बुलाया। पति ने बेंच के सामने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है। इस उम्र में अकेला कहां जाएगा? पति ने कहा- मैं आज भी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं। मैं उसके मायके में भी रहने को तैयार हूं। जब से उसकी नौकरी लगी है, वह बदल गई है। दूसरे मामले में पति ने अपनी पत्नी पर एक महिला के साथ अवैध संबंध रखने के आरोप लगाए। पति ने कहा- मुझे पत्नी से जान का खतरा है। इसके उलट पत्नी ने पति पर उसकी अश्लील फोटो

वायरल करने, जबरन अबॉर्शन कराने और दहेज के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। ये दोनों केस सोमवार को भोपाल में महिला आयोग में पेंडिंग मामलों की जनसुनवाई के दौरान सामने आए।

विधानसभा में 7,765 करोड़ का अनुपूरक बजट हुआ पेश

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

भोपाल, एजेंसी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में मंगलवार को 7,765 करोड़ रुपये से अधिक का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें भावांतर योजना के लिए सर्वाधिक 2,313 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में नर्मदा घाटी विकास की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं तथा भू-अर्जन के लिए तीन हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जन का काम करने वाली संस्थाओं को 2220.62 करोड़ रुपये दिए गए

हैं। केंद्रीय सड़क निधि, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण, उन्नयन, भू-अर्जन के लिए मुआवजा, वृहद पुलों का निर्माण, सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए लोक निर्माण विभाग को 1,300 करोड़ रुपये अतिरिक्त तौर पर दिए जाएंगे। प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप देने के लिए 258.07 करोड़, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 50 करोड़, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन के लिए 30.00 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए 25 करोड़, पीएम ई-बस सेवा योजना के लिए 21.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

संपादकीय

मुफ्त की राजनीति बनाम राष्ट्र निर्माण

लोकतांत्रिक राजनीति में घोषणापत्र के जरिए चुनावी वादे नई बात नहीं। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में सरकारी खजाने से मुफ्त सुविधाएं, नकद सहायता और अन्य 'फ्रीबीज' की घोषणाओं का चलन नया है। इन पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। वहीं, जब भी चुनावी मौसम आता है, इस मुद्दे पर चर्चा फिर से गर्म हो जाती है। फ्रीबीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका पिछले चार वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अदालत को बताया कि 2022 में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस गया, पर नियमित सुनवाई शुरू नहीं हुई। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने लंबित मामलों के भारी बोझ का हवाला दिया और तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि उचित समय पर सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से मुफ्त योजनाओं का वादा और मुफ्त उपहार देना (फ्रीबीज) मतदाताओं को अनुचित ढंग से प्रभावित करने का माध्यम बनता है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि फ्रीबीज देने वाले राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न जब्त किए जाएं या उनका पंजीकरण रद्द किया जाए। वैकल्पिक रूप से केंद्र सरकार को कानून बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका के मुताबिक, सरकारी खजाने से मुफ्त वस्तुएं या सेवाएं देने के चुनावी वादे चुनावी रिश्वत (इलेक्टोरल ब्राइबरी) जैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर फ्रीबीज को लेकर गंभीर चिंता जताता रहा है। इसी साल 19 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि यदि कोई राज्य रेवेन्यू सरप्लस में है, तो उसकी प्राथमिकता सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसे बुनियादी ढांचे का विकास क्यों नहीं है? अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आते ही नई योजनाओं की घोषणाएं क्यों शुरू हो जाती हैं और राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। इससे पहले 3 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विशेषज्ञ समिति गठित करने के संकेत दिए थे और कहा था कि लगभग सभी राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं का वादा करते हैं, इसलिए इस विषय पर खुली चर्चा से बचते हैं। 11 अगस्त 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि करदाताओं को यह सवाल उठाने और जानने का अधिकार है कि उनके कर का पैसा बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च हो या मुफ्त योजनाओं पर। वहीं, 12 फरवरी 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने चुनावी मुफ्त योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, न कि परजीवी वर्ग में तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन, नकद सहायता लोगों में काम करने की इच्छा पर असर डालते हैं। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।

ज्ञान-विज्ञान

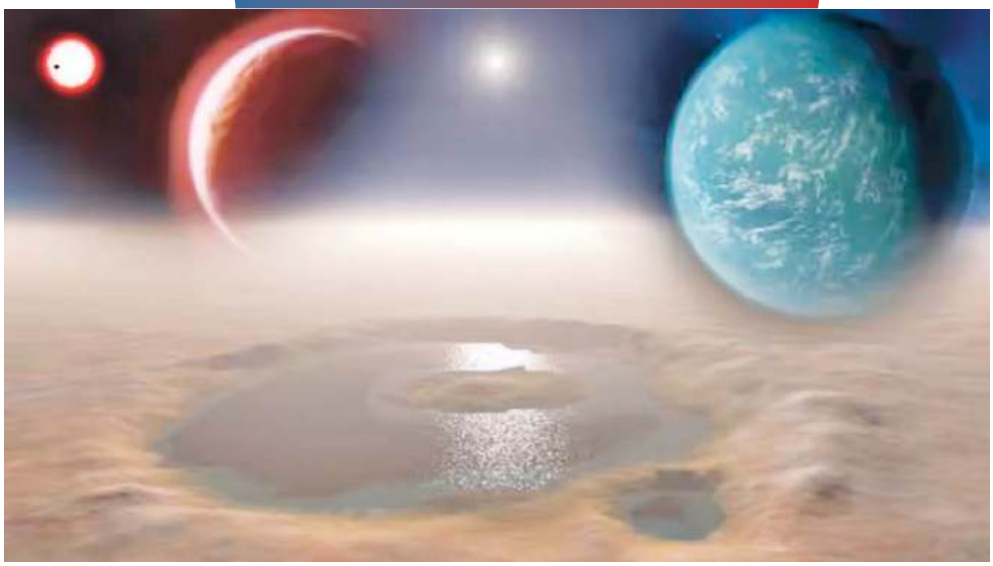

पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश पूरी?

नासा को मिले पक्के वायुमंडल के सबूत, एक और ग्रह पर बसेगी दुनिया?

हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की खोज में एक नया मोड़ आया है। रिसर्चर्स ने 49 प्रकाश-वर्ष दूर पृथ्वी जैसे एक ग्रह के चारों ओर एक वायुमंडल का पता लगाया है, जिसकी सतह पर तरल पानी हो सकता है। पथरीले एक्सोप्लैनेट के चारों ओर भी ऐसे घेरे के संकेत मिले हैं, जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र (हैबिटेबल जोन) के बाहर स्थित हैं। यह वह क्षेत्र है, जहां ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। इसलिए वहां पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना हो सकती है।

इससे पहले गैस वाले बड़े एक्सोप्लैनेट और सब-नेपच्यून के चारों ओर वायुमंडल पाए गए हैं लेकिन यह नई खोज अलग है। स्टडी के मुख्य लेखक डॉक्टर कॉलिन चेरुबिम ने बताया है कि यह हमारे सौर मंडल के बाहर रहने योग्य क्षेत्र में स्थित एक पथरीले ग्रह पर वास्तव में ऑब्जर्वेशन से कन्फर्म हुआ पहला वायुमंडल है।

'कई मामलों में पृथ्वी के समान'

डॉक्टर कॉलिन चेरुबिम के मुताबिक, यह वास्तव में एक रोमांचक खोज है। मुझे लगता है कि यह LHS 1140b को हमारे सौर मंडल के बाहर एस्ट्रोबायोलॉजी और रहने की क्षमता के अध्ययन के लिए यह सबसे आशाजनक और रोमांचक प्रयोगशाला के रूप में सबसे आगे रखती है। LHS 1140b ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 5.6 गुना है और इसकी त्रिज्या 70% बड़ी है। चेरुबिम ने बताया कि यह कुछ मामलों में पृथ्वी के समान है। जैसे इसकी कुल बनावट और तापमान। कुछ मामलों में यह अलग है। जैसे- यह टाइडली लॉक्ड है, इसमें बहुत अधिक पानी हो सकता है। इसका वायुमंडल बहुत अलग है। नई स्टडी से अब हमें पता चला है कि LHS 1140b में रहने लायक माहौल के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद हैं। यह एक चट्टानी ग्रह है, यहां का तापमान ऐसा है कि तरल पानी रह सकता है और यहां एक ऐसा वायुमंडल है जो पानी को उड़ने से रोकता है। इसका तारा शांत है और उसमें बहुत कम फ्लेयर्स (ऊर्जा विस्फोट) होते हैं।

यह एक शानदार खोज

2017 में खोजा गया यह ग्रह अपेक्षाकृत पास है और सेटस (समुद्री राक्षस) तारामंडल में एक छोटे लाल बौने तारे (रेड ड्वार्फ) की परिक्रमा करता है। यह तारा हमारे अपने सूर्य से छोटा और कम चमकदार है लेकिन अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा आयनकारी विकिरण के रूप में छोड़ता है। चेरुबिम ने यह खोज जारी रखने के लिए, खासकर जीवन के संकेत खोजने के लिए, एक बहुत ही रोमांचक जगह है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स की प्रोफेसर जेन बर्कबी ने कहा कि यह शानदार खोज है। छोटे रेड ड्वार्फ तारे सबसे आम तरह के तारे होते हैं। इसलिए उनके रहने लायक जोन में मौजूद चट्टानी एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने का हमारे पास सबसे अच्छा मौका होता है। वे अक्सर बहुत सक्रिय होते हैं। वे अपने आस-पास मौजूद ग्रहों का वायुमंडल उड़ा ले जाते हैं, जिससे चट्टानी ग्रहों पर या तो बहुत पतला वायुमंडल बचता है या फिर हवा बिल्कुल नहीं रहती। नीदरलैंड्स की लीडेन ऑब्जर्वेटरी की डॉक्टर यामिला मिगुएल ने भी इन नतीजों का स्वागत किया और कहा कि यह पहले से ही पता था कि अपने होस्ट स्टार के करीब मौजूद ग्रह अंतरिक्ष में अपनी वायुमंडलीय गैसें खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह ग्रह इसलिए इतना दिलचस्प है क्योंकि यह इतनी ज्यादा मात्रा में वायुमंडल खो रहा है। हम यहां से इसका पता लगा सकते हैं, जो कि एक छोटे और पथरीले ग्रह के मामले में आसान नहीं है।

Assam

असम में बाढ़ ने मचाई तबाही, 24 घंटे के अंदर 31 मौतें, 6 लाख बेघर, शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट समेत 16 जिले डूबे

गुवाहाटी, (एजेंसी) असम के विभिन्न जिलों में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं तथा सेना समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं क्योंकि असम के कुछ हिस्सों में पटरियां बाढ़ के कारण जलमग्न हैं। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में असम में बाढ़ से कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 31 हो गई है। ASDMA की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में शिवसागर जिले में 13,

चराइदेव में पांच, गोलाघाट में दो और जोरहाट में एक व्यक्ति की मौत हुई। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें गोलाघाट, कामरूप, होजई, डिब्रूगढ़, विश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदलगुरी, नागांव, चराइदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और शिवसागर सहित 16 जिलों में 5.64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

शिवसागर में 3.59 लाख प्रभावित- बाढ़ का पानी 24,210.35 हेक्टेयर फसल क्षेत्र में भर गया है और 44 राजस्व मंडलों (रेवेन्यू सर्कल्स) के 872 गांवों को प्रभावित किया है। शिवसागर सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है, जहां 3.59 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

Uttarpradesh

राम मंदिर ट्रस्ट में कौन लेगा चंपत राय की जगह! खाली हुए तीन पदों पर इन नामों की चर्चा

अयोध्या, (एजेंसी) चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट (Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) को लेकर बड़ी खबर है. विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल बागड़ा ट्रस्ट में महासचिव बन सकते हैं. चंपत राय के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था. इसके अलावा अन्य दो खाली पदों पर किन नामों पर विचार हो रहा है वो भी सामने आया है.

ट्रस्ट बुधवार को दोपहर में राम मंदिर परिसर में एक खास बैठक करने वाला है. इसके बाद मणिराम छावनी में उसकी नियमित बैठक होगी.

ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक, एजेंडा में नए महासचिव की नियुक्ति, ट्रस्टी के तीन खाली पदों को भरना और मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के लिए चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शामिल है. बैठक में दान में कथित हेराफेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई SIT रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है. राम मंदिर में चढ़ावे के तौर पर मिले नोटों की गिनती और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल होगी.

दान चोरी के विवाद के बाद पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे और ट्रस्टी बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के कारण ये पद खाली हुए थे. चंपत राय के इस्तीफे के बाद फिलहाल कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया हुआ है.

New Delhi

रेलवे की बढ़ेगी रफ्तार, 300 स्टॉपेज खत्म होंगे; लिस्ट में किन स्टेशनों और ट्रेनों के नाम

नई दिल्ली, (एजेंसी) भारतीय रेलवे जल्द ही लंबी दूरी और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार में बड़ा इजाफा करने जा रही। इसके लिए देश भर में प्रायोगिक आधार पर दिए गए 300 से अधिक स्टॉपेज को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का खाका तैयार किया है। इससे यात्रियों का यात्रा समय 15 से 45 मिनट तक घटेगा। नई व्यवस्था अक्तूबर 2026 तक लागू होगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सांसदों व विधायकों) की सिफारिशों और क्षेत्रीय जनता की मांग पर सैकड़ों स्टेशनों पर छह महीने के प्रायोगिक आधार पर ट्रेनों के ठहराव मंजूर किए गए थे। इसका उद्देश्य छोटे कस्बों और स्टेशनों के यात्रियों को सीधी रेल कनेक्टिविटी देना था। नियम के मुताबिक छह महीने की मियाद पूरी होने के बाद टिकटों की बिक्री और व्यावसायिक उपयोगिता की समीक्षा की जानी थी। रेलवे बोर्ड के जीरो-कॉमर्शियल-स्टॉपेज मूल्यांकन ढांचे और इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईसीएमएस) के ताजा आंकड़ों में पाया गया कि ये 300 से अधिक स्टॉपेज बोर्ड के न्यूनतम 15 टिकट प्रति ट्रेन प्रति दिन के व्यावसायिक पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं। अधिकारी ने बताया कि कम यात्री मिलने के कारण ट्रेनों को अनावश्यक रूप से रोकने से न केवल करोड़ों रुपये की बिजली और ईंधन बर्बाद हो रहा था।

Sikkim

सिक्किम की सुरंग में लैंडस्लाइड के बाद अब तक 20 की मौत, 5 लोगों की तलाश जारी

सिक्किम, (एजेंसी) सिक्किम के नामची जिले में समरडुंग स्थित एनएचपीसी (NHPC) तीस्ता स्टेज VI जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में सोमवार दोपहर एक बजे संदिग्ध मीथेन गैस के अचानक विस्फोट से सुरंग ढह गई. इस हादसे में फंसे 25 मजदूरों में से कम से कम 20 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 5 अन्य मजदूर पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं.

नामची की पुलिस अधीक्षक सोनम डी भूटिया ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव ऑपरेशन के दौरान अब तक 12 शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें से 7 की पहचान हो चुकी है और बाकी शवों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं.

चट्टान में फंसी मीथेन गैस में हुआ

विस्फोट- NHPC द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, चट्टानों के अंदर फंसी हुई संदिग्ध मीथेन गैस के अचानक फटने से विस्फोट हुआ, जिसके बाद वहां घना धुआं और जहरीली गैसें फैल गईं. हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि मीथेन गैस विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा.

खेल

घरेलू सत्र से पहले प्लेइंग कंडीशंस में हुए बदलाव, गेंदबाज को जानबूझकर नो बॉल करना किस तरह पड़ेगा भारी?

नई दिल्ली, (एजेंसी) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2026-27 घरेलू सत्र से पहले प्लेइंग कंडीशंस में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिसमें जानबूझकर नो बॉल करने वाले गेंदबाज को पूरे मैच से निलंबित करना प्रमुख है। कोई गेंदबाज अगर जानबूझकर फ्रंट-फुट नो-बॉल या ऐसी गेंद फेंकता है जिसमें उसका पैर निर्धारित स्थान पर नहीं पड़ता तो उसे केवल उस पारी से नहीं, बल्कि पूरे मैच के शेष हिस्से से गेंदबाजी करने से निलंबित कर दिया जाएगा। अब तक लागू नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में गेंदबाज को केवल संबंधित पारी से गेंदबाजी करने से रोका जाता था।

बीसीसीआई ने हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) द्वारा सुझाए गए इन संशोधनों को सभी राज्य क्रिकेट संघों के साथ साझा कर दिया है। बीसीसीआई के परिपत्र के अनुसार, खेल परिस्थितियों के

नियम 41.8 में बदलाव के तहत किसी गेंदबाज को पूरे मैच से निलंबित करने का निर्णय मैदान पर मौजूद अंपायर लेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन दिन के खेल की समाप्ति से जुड़ा है। नए नियम के अनुसार अगर दिन के अंतिम ओवर के दौरान विकेट गिरता है, तब भी वह ओवर पूरा कराया जाएगा। अभी तक अंतिम ओवर के बीच में विकेट गिरने पर उसी समय स्टंप्स घोषित कर दिए जाते थे।

एमसीसी का मानना था कि नियम 12.5.2 के कारण दिन के अंत में नई बल्लेबाज को क्रीज पर आने का अवसर नहीं मिल पाता था। इसी वजह से इसमें संशोधन किया गया है। इसके अलावा अब किसी मैच की अंतिम पारी में कोई भी टीम पारी घोषित या पारी छोड़ने (फॉरफिट) का विकल्प नहीं अपना सकेगी। नियम 15.2 में यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि शासी निकायों का मानना था कि इस प्रावधान का उपयोग बनावटी परिणाम हासिल करने के लिए किया जाता था, जो खेल की भावना के अनुरूप नहीं है।

वनडे घरेलू मुकाबलों में अब टीम के मुख्य कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर प्रवेश की अनुमति होगी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी आईसीसी इसी प्रकार का नियम लागू करने का प्रस्ताव दे चुका है। विकेटकीपरों को भी नए नियमों के तहत कुछ राहत मिली है। अब उन्हें केवल गेंद डाले जाने के क्षण में ही अपने दस्ताने स्टंप्स के पीछे रखने होंगे। पहले गेंदबाज के रनअप शुरू करते ही विकेटकीपर को पूरे समय अपने दस्ताने स्टंप्स के पीछे रखने होते थे। इस नियम के कारण पहले कई बार गेंद को नो-बॉल करार दिया गया या स्टंपिंग अमान्य हो गई थी। अगले महीने दलीप ट्रॉफी से शुरू होने वाले घरेलू सत्र से पहले राज्य क्रिकेट संघों ने अंपायर और मैच रेफरी को नए नियमों की जानकारी देना शुरू कर दिया है। बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार, मैच अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

सिनेमा

'डूम्सडे' की सबसे बड़ी तैयारी! Spider Man-Endgame दोनों बने हथियार?

मार्वल फैंस के लिए पिछले कुछ साल सचमुच अच्छे नहीं निकले थे. मल्टीवर्स सागा ने कई सारे लोगों का सिर चकरा डाला था, जिसके बाद MCU की फिल्मों के लिए उत्सुकता कम होने लगी. मगर अब लगता है कि वो दिन जा चुके हैं. मार्वल अपने पुराने फॉर्म में लौटने की तैयारी शुरू कर चुका है, जिसमें उसकी सबसे बड़ी कड़ी इस समय एवेंजर्स डूम्सडे है. फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे इस समय MCU की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवन्स की वापसी हो रही है. सच कहें तो जबसे ये दोनों गए हैं, तबसे मार्वल के लिए सब मटियामेट हो चुका था. लेकिन इन दोनों का अब एक दिलचस्प मोड़ में वापस आना सचमुच मार्वल फैंस के लिए राहत की सांस है. दो दिन पहले डूम्सडे का ट्रेलर भी रिलीज हुआ, जिसने फैंस की उम्मीदें कई गुना बढ़ा दी हैं. मार्वल इस फिल्म से एक बड़े कमबैक की तैयारी में जुटा है. लेकिन इतने बड़े कमबैक से पहले, वो दो कदम पीछे भी लेने वाला है. डूम्सडे से पहले, MCU की तरफ से दो बड़ी फिल्में स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे और एवेंजर्स एंडगेम थिएटर्स में लगने वाली हैं.ये दोनों की फिल्में डूम्सडे में होने वाली सारी हरकतों को सही से सेटअप करने वाली हैं. यानी दोनों ही फिल्मों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. तो चलिए, हम आपको इन दोनों फिल्मों से मार्वल का क्या प्लान है, ये समझाने की कोशिश करते हैं.

Highlights

1. Citizens deserve to be heard with dignity: Huma Qureshi on CPJ protest march
2. It was fine, it's always fine: JP Nadda on meeting with CJP leaders
3. PM Modi speaks on NEET paper leak after CJP protest, says 'We stand with students'
4. Basketball pole falls onto 24-year-old in Gurugram, he suffers 3 spinal fractures
5. Water cannons used against protesters demanding Pradhan's resignation in Kerala
6. Abhijeet Dipke sets a new condition for talks with the government
7. Police file 5 FIRs over violence during CJP march, to examine over 250 videos

Google and India's AI ambition, with an inkling of new beginnings

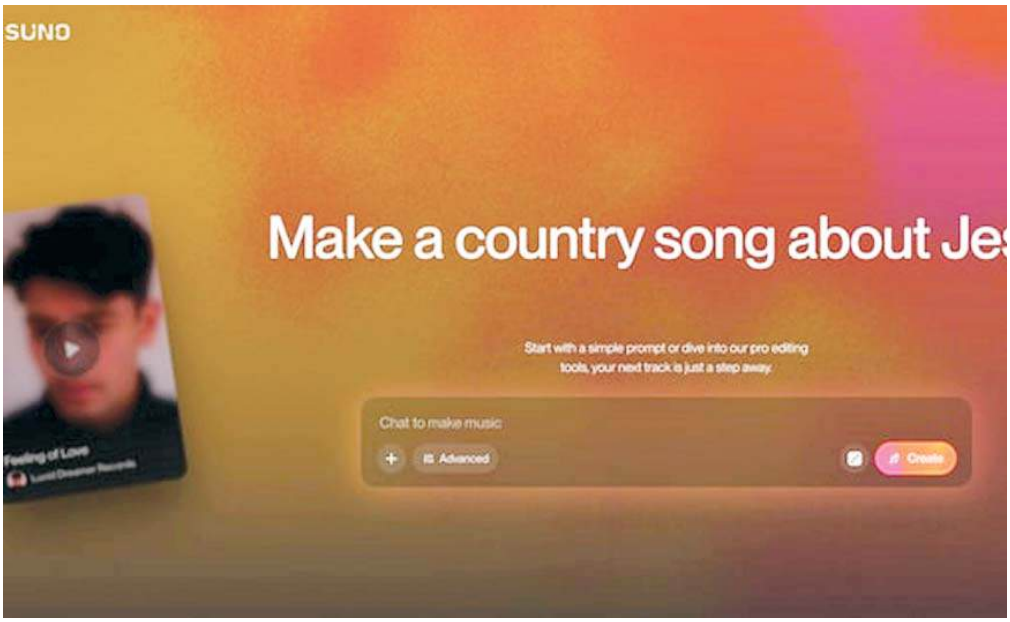

NEW DELHI, (Agency). Cognitive warmup. The big secret is out. We finally know AI music generation company Suno trained its models. One of the largest in terms of what they do, here's a sketch that has been found of the millions of songs and lyrics they have scraped from various sources. 113,879 hours of YouTube Music, 62,117 hours of Pond5, and 12,287 hours of Deezer, to name a few. There is also audio from stock music libraries Pond5, Jamendo, Freesound, and the International Music Score Library Project, as well as podcasts via RSS feeds.

Suno has faced several lawsuits in recent years from the recording industry, mostly around using copyright data for training AI models. UMG, Sony, Warner Music Group, and the Production Music Library, all have been at loggerheads with Suno (or continue to be) at some stage. Suno's most profound argument so far has been that it's used "essentially all music files of reasonable quality that are accessible on the open internet".

SAFETY, IN AN AGENTIC FUTURE

I have, time and detail, illustrated Google's intent to making AI relevant for the masses in India. That includes real-world implementations across education, agriculture, healthcare and so on. This week, I'd like to circle back to an announcement from the I/O Connect India 2026...one that specifically talks about India's cybersecurity apparatus in the era of AI agents.

"The agentic era extends that responsibility. Software can now interpret intent, use tools and take action autonomously. This gives developers extraordinary speed, but it also changes what must be secured. Safety can no longer be a final checkpoint before launch. It must be part of the underlying architecture from day one, shaping how agents are built and how they interact," Google India says, in a statement.

There are three key initiatives Google has embarked on in India, for this.

Google says they are making their specialised cybersecurity agent, Sec-Gemini v3, available to trusted government and enterprise testers including Flipkart. Sec-Gemini can reason across complex security data and help teams investigate incidents rapidly. This will be relevant for Indian enterprises and government services systems, amidst higher threat perception.

For this, Google references the Big Sleep vulnerability research agent developed by Google DeepMind and Project Zero, and says that it can be useful in identifying software vulnerabilities. They also talk about the CodeMender agent that can automatically write security fixes and contribute directly to open-source projects. July 2025 marked a moment for the Big Sleep AI agent. "We believe this is the first time an AI agent has been used to directly foil efforts to exploit a vulnerability in the wild," said Sandra Joyce, VP, Google Threat Intelligence, at the time.

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर की सलाह दी, जमानत पर फैसला 23 को

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

इंदौर। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी उसकी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने की सलाह दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सोनम के वकील से कहा- उनके पास दो विकल्प हैं-

पहला- यदि वे चाहें तो यह अदालत मेघालय सरकार की अपील पर उनकी दलीलें सुनकर अंतिम आदेश पारित कर सकती है। दूसरा- सोनम फिलहाल आत्मसमर्पण करे ताकि जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकें और इस दौरान जमानत के मुद्दे पर भी विचार किया जा सके। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को करेगी। उसी दिन यह फैसला हो सकता है कि सोनम की जमानत बरकरार रहेगी या उसे जेल जाना होगा। इसी साल 26 अप्रैल को मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को जमानत दी थी। मेघालय सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने वारदात के बाद सोनम के व्यवहार और कानूनी तर्कों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि गिरफ्तारी के समय कारण नहीं बताए जाने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया? इस पर सोनम के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा और कहा कि वे गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। वहीं, मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसने पुलिस के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था। ऐसे में बाद में यह कहना कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी मेमो में यदि कोई कमी है तो वह केवल लिपिकीय त्रुटि (क्लेरिकल मिस्टेक) है। जो आरोपी स्वयं पुलिस के सामने उपस्थित होकर समर्पण करता है, वह गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी आधारों पर राहत नहीं मांग सकता।

10 करोड़ के लोन का झांसा देकर एक करोड़ ठगे

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

इंदौर। एक बड़े कारोबारी से 10 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। अब इस मामले में जिला कोर्ट के आदेश पर पीड़ित को पूरी राशि वापस मिल गई है। कोर्ट के निर्देश के बाद बैंक ने आरोपियों के खातों में फ्रीज किए गए 1 करोड़ रुपए कारोबारी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। साइबर ठगी के मामले में इतनी बड़ी राशि की वापसी इंदौर जिला कोर्ट में अपने तरह का अहम मामला माना जा रहा है। दरअसल, कारोबारी को अपने व्यवसाय के लिए 10 करोड़ रुपए के लोन की जरूरत थी। उसने कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों में आवेदन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान चेन्नई की एक कंपनी के प्रतिनिधियों ने संपर्क कर 10 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का दावा किया। आरोपियों ने जरूरी दस्तावेज मंगवाकर कारोबारी को चेन्नई बुलाया। वहां भरोसा जीतने के लिए 10 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) दिखाया और लोन मंजूर होने का दावा करते हुए कई दस्तावेजों, चेक और स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए। आरोपियों ने प्रोसेसिंग फीस, ब्याज, रजिस्ट्रेशन और अन्य बैंकिंग औपचारिकताओं का हवाला देकर करीब 1 करोड़ रुपए जमा करवा लिए। रकम मिलते ही डिमांड ड्राफ्ट वापस ले लिया गया और लोन जारी करने के नाम पर टालमटोल शुरू हो गई। लंबे समय तक रकम नहीं मिलने पर कारोबारी को ठगी का अहसास हुआ।

गैस पाइपलाइन हादसे में पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

इंदौर। विजय नगर स्थित अवंतिका गैस पाइपलाइन में 23 जून को हुए हादसे को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में पेश हुए एसीपी पराग सैनी ने कोर्ट को जानकारी दी गई कि इस मामले में वार्ड 31 के बीजेपी पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज कर आरोपी बना लिया गया है।

नगर निगम की रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया था कि निगम की ओर से बोरिंग नहीं कराई कराई जा रही थी। झुलसे लोगों की ओर से वकीलों ने बताया कि अभी तक उन्हें इलाज की राशि नहीं मिली है। साथ ही अभी भी इलाज जारी है। इस पर कोर्ट ने शासन को कहा कि झुलसे लोगों के इलाज की राशि का पेमेंट रिफंड करवाएं। शासन की ओर से एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में राशि इलाज के बाद जारी होती है, इस पर पीड़ितों की ओर से कहा गया कि अभी तो अस्पताल को उनके इलाज की राशि चाहिए जो हमें खर्च करना पड़ रही है। इस कोर्ट ने शासन को जल्द राशि रिलीज करने के लिए निर्देशित किया। सुनवाई के दौरान बताया गया कि नगर निगम की रिपोर्ट अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। एसीपी ने बताया कि अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर कोर्ट ने समन्वय बनाने की बात कही। मामले में चार्जशीट को लेकर पुलिस की ओर से बताया कि कंटेंट क्रिएटर गिरी राजकुमारी उर्फ जिनी झाला अभी अहमदाबाद के अस्पताल में एडमिट है। उनके बयान होना है। सुनवाई में पीड़ित झुलसे लोगों की ओर से वकीलों ने बताया कि अभी तक उन्हें इलाज की राशि नहीं मिली है। साथ ही अभी भी इलाज जारी है। इस पर कोर्ट ने शासन को कहा कि झुलसे लोगों के इलाज की राशि का पेमेंट रिफंड करवाएं।

डबल डेकर ब्रिज आज से शुरू

@ डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट

इंदौर। शहर के सबसे व्यस्त जंक्शन में से एक लवकुश चौराहे पर हर दिन सफर करने वाले 50 हजार से अधिक वाहन चालकों के लिए खुशखबरी है। चौराहे पर बनकर तैयार हुए बहुप्रतीक्षित डबलडेकर फ्लायओवर की पहली लेन अरबिंदो से बाणगंगा तरफ बुधवार से शुरू की जा रही है।

इस लेन के चालू होते ही रोजाना चौराहे पर गुत्थमगुत्था हो रहे ट्रैफिक को बड़ी राहत मिलेगी। आईडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े के मुताबिक, रोड की सेफ्टी और व्हीकल टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अस्थायी तौर पर लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है और बुधवार से इस पर ट्रैफिक की आवाजाही आधिकारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी। इंदौर के इतिहास में प्रथम बार अरविंदो से बाणगंगा की तरफ जाने वाले पुल से वाहनों की आवाजाही कल से आरंभ होने जा रही है। इस पुल की विशेषता है कि यह डबल डेकर पुल है। यह नगर का प्रथम पुल है जो डबल है, इस पुल से मेट्रो भी गुजरेगी। इस पुल की एक लाइन आरंभ होने से यातायात पर काफी सुगम होने की संभावना है। आगामी सिंहस्थ में इस पुल से यात्रियों को काफी लाभ होगा। 1454 मीटर लंबा यह पुल 6 लाइन का होगा, पुल के नीचे मेट्रो लाइन रहेगी। 175 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है। यह प्रदेश का प्रथम डबल डेकर पुल है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इस पुल का निर्माण किया है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक - पुष्पेंद्र पुष्प द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग एलयूएन-22, सेक्टर एफ, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर से मुद्रित एवं इंडस्ट्री हाउस 15 ए.बी. रोड, ओल्ड पलासिया, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। ■ आर.एन.आई. नंबर MPBIL/2015/66535 ■ डाक पंजीयन : एमपी/आईडीसी/1600/2023-2025 ■ प्रधान संपादक - पुष्पेन्द्र पुष्प, ■ फोन : 7312433667, मो.नं. 9826044334 ■ पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार। ■ न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा।
इस समाचार पत्र में प्रकाशित विभिन्न समाचार, सूचनाएं, आलेख एवं विचार लेखकों के अपने है तथा विभिन्न समाचार एजेंसियों एवं स्त्रोतों से प्राप्त किए गए हैं अतः इनसे प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है- संपादक